

https://farid.ps/articles/israel_apartheid_not_democracy/hi.html

इज़राइल एक रंगभेदी राज्य के रूप में, न कि लोकतंत्र

इज़राइल को एक लोकतांत्रिक राज्य के रूप में चित्रित करना लंबे समय से उसकी अंतरराष्ट्रीय छवि का एक आधारशिला रहा है, जो इसके संसदीय तंत्र, चुनावों और कानूनी ढांचे में निहित है। हालांकि, विशेष रूप से फलस्तीनियों के प्रति इसकी नीतियों की बारीकी से जांच करने पर एक व्यवस्थित भेदभाव और अलगाव की संरचना सामने आती है, जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों की तुलना में रंगभेद (अपार्थेड) के साथ अधिक संरेखित है। यह निबंध तर्क देता है कि इज़राइल एक सच्चे लोकतंत्र के बजाय एक रंगभेदी राज्य के रूप में कार्य करता है, जो मानवाधिकार संगठनों, कानूनी ढांचों और हाल के राजनीतिक विकासों द्वारा उजागर किए गए व्यवस्थित भेदभाव, असहमति के दमन, और यहूदी इज़राइलियों और फलस्तीनियों के बीच अधिकारों में स्पष्ट असमानताओं के साक्ष्य पर आधारित है।

व्यवस्थित भेदभाव और रंगभेद

1973 के रंगभेद सम्मेलन के अनुसार, रंगभेद एक ऐसी संस्थागत नस्लीय अलगाव और भेदभाव की व्यवस्था है, जिसे एक नस्लीय समूह की दूसरे पर प्रभुत्व बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की 2024 की रिपोर्ट, **इज़राइल का फलस्तीनियों के खिलाफ रंगभेद**, इस लेबल के लिए एक विस्तृत तर्क प्रस्तुत करती है, जिसमें तर्क दिया गया है कि इज़राइल का फलस्तीनियों के साथ व्यवहार—भेदभाव, संपत्ति छीनने और दमन के माध्यम से—एक ऐसी व्यवस्था का गठन करता है जो फलस्तीनियों की कीमत पर यहूदी इज़राइलियों को प्राथमिकता देता है। रिपोर्ट में ऐसी नीतियों को रेखांकित किया गया है जैसे भूमि अधिग्रहण, घरों का विध्वंस, और पानी और बिजली जैसे संसाधनों तक सीमित पहुंच, जो इज़राइल, वेस्ट बैंक और गाजा में फलस्तीनियों को असमान रूप से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, वेस्ट बैंक में, यहूदी बसने वाले पूर्ण नागरिकता अधिकारों का आनंद लेते हैं, जबकि फलस्तीनी सैन्य कानून के तहत रहते हैं, जिन्हें बुनियादी स्वतंत्रताएं जैसे आवागमन और राजनीतिक भागीदारी से वंचित रखा जाता है। यह दोहरा कानूनी तंत्र—यहूदियों के लिए सिविल कानून और फलस्तीनियों के लिए सैन्य कानून—दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद की नस्लीय अलगाव को दर्शाता है, जहां अधिकार नस्ल के आधार पर आवंटित किए जाते थे।

इसके अलावा, 2018 का राष्ट्र-राज्य कानून, जो इज़राइल को “यहूदी लोगों का राष्ट्र-राज्य” घोषित करता है, स्पष्ट रूप से यहूदी पहचान को सभी नागरिकों के लिए समान अधिकारों पर प्राथमिकता देता है। यह कानून अरबी को आधिकारिक भाषा से हटा देता है और यहूदी बस्तियों को राष्ट्रीय मूल्य के रूप में बढ़ावा देता है, जिससे इज़राइल की 20% आबादी जो अरब है, प्रभावी रूप से हाशिए पर चली जाती है। ऐसी नीतियां समान नागरिकता के लोकतांत्रिक सिद्धांत को कमजोर करती हैं, क्योंकि वे कानून में यहूदी सर्वोच्चता को स्थापित करती हैं, जो रंगभेदी व्यवस्थाओं की एक विशेषता है जहां एक समूह के अधिकार जातीयता या नस्ल के आधार पर दूसरे से अधिक होते हैं।

असहमति और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का दमन

एक कार्यशील लोकतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और समान राजनीतिक भागीदारी की गारंटी देता है, लेकिन इज़राइल का फलस्तीनी नागरिकों और उनके प्रतिनिधियों के साथ व्यवहार एक स्पष्ट विरोधाभास को उजागर करता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की 2022 की ब्रिफिंग, **निर्वाचित लेकिन प्रतिबंधित: इज़राइल की knesset में फलस्तीनी सांसदों के लिए सिकुड़ती जगह**, यह दस्तावेज करती है कि कैसे फलस्तीनी knesset सदस्य (MKs) भेदभावपूर्ण नियमों का सामना करते हैं जो उनके निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने की उनकी क्षमता को सीमित करते हैं। उदाहरण के लिए, फलस्तीनी MKs द्वारा प्रस्तावित विधेयक जो उनकी समुदाय के अधिकारों को संबोधित करते हैं, चर्चा से पहले अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं, और 2016 का निष्कासन कानून knesset को “नस्लवाद के लिए उकसाने” या “सशस्त्र संघर्ष का समर्थन” करने के लिए MKs को हटाने की अनुमति देता है, एक प्रावधान जो अक्सर अरब MKs को निशाना बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। MK ओफर कासिफ का मामला, जिन्हें 2024 में दक्षिण अफ्रीका के इज़राइल के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में नरसंहार के मामले का समर्थन करने के लिए निष्कासन का सामना करना पड़ा, इस दमन का उदाहरण है। हालांकि निष्कासन की कोशिश विफल रही, कासिफ को छह महीने के लिए निलंबित कर दिया गया, एक ऐसा कदम जिसे आलोचकों का कहना है कि असहमति को चुप कराने के लिए राजनीतिक रूप से प्रेरित था।

अरब MKs का निलंबन एक बार-बार दोहराया जाने वाला पैटर्न रहा है, जो हदाश-तआल और रआम जैसे अरब दलों को असमान रूप से प्रभावित करता है। 2023 में, आइदा तौमा-स्लिमन और इमान खतीब-यासिन को गाजा में इज़राइली सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करने के लिए क्रमशः दो महीने और एक महीने के लिए निलंबित किया गया। ऐतिहासिक मामले, जैसे हनीन ज़ोआबी के बार-बार निलंबन (उदाहरण के लिए, 2014 में फलस्तीनी प्रतिरोध का समर्थन करने वाले बयानों के लिए छह महीने), इस प्रवृत्ति को और स्पष्ट करते हैं। ये कार्रवाइयां उन यहूदी MKs के लिए जवाबदेही की कमी के साथ तीव्र विरोधाभास में हैं जो उक्सावे में शामिल होते हैं, जैसे 2023 के यरुशलम ध्वज मार्च के दौरान, जहां प्रतिभागियों ने “अरबों को मारो” के नारे लगाए बिना समान परिणामों का सामना किए। यह दोहरा मापदंड—अरब MKs को उनके भाषण के लिए दंडित करना जबकि यहूदी राष्ट्रवादियों द्वारा उक्सावे को सहन करना—कानून के तहत समान व्यवहार के लोकतांत्रिक सिद्धांत को कमजोर करता है और एक ऐसी व्यवस्था का सुझाव देता है जो अल्पसंख्यक आवाजों को दबाने के लिए डिज़ाइन की गई है, जो लोकतंत्र के बजाय रंगभेद की विशेषता है।

अधिकारों और जीवन स्थितियों में असमानताएं

इज़राइली नियंत्रण के तहत फलस्तीनियों के जीवित अनुभव लोकतंत्र के दावे को और कमजोर करते हैं। गाजा में, जैसा कि 25 मई 2025 को UNRWA के पोस्ट में उजागर किया गया, नाकाबंदी और बार-बार की सैन्य कार्रवाइयों ने एक मानवीय संकट पैदा किया है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र ने और अधिक आपदा को रोकने के लिए प्रतिदिन 500-600 सहायता ट्रकों की मांग की है। गाजा में स्वास्थ्य सुविधाओं पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की रिपोर्ट चिकित्सा बुनियादी ढांचे पर हमलों, विशेष रूप से बाल चिकित्सा और नवजात देखभाल, को जीवन और स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लंघन के रूप में दस्तावेज करती है, जो संभावित रूप से मानवता के खिलाफ अपराधों के बराबर हो सकता है। ये स्थितियां, प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल के जानबूझकर किए गए विनाश के साथ मिलकर, फलस्तीनियों को असमान रूप से प्रभावित करती हैं, जो यहूदी इज़राइलियों के लिए उपलब्ध अधिकारों और सेवाओं के साथ एक स्पष्ट विरोधाभास पैदा करती हैं।

इज़राइल के भीतर, फलस्तीनी नागरिकों को आवास, शिक्षा और रोजगार में व्यवस्थित भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एमनेस्टी द्वारा उल्लिखित घरों के विध्वंस की प्रथा विस्थापन का एक प्रमुख तंत्र है, जिसमें फलस्तीनी परिवारों को निर्माण परमिट से वंचित किया जाता है जबकि यहूदी बस्तियां विस्तार करती हैं। पूर्वी यरुशलम में, फलस्तीनियों को अक्सर निवास के अधिकारों से वंचित किया जाता है, जबकि यहूदी बसने वालों को तरजीही व्यवहार दिया जाता है। ये असमानताएं संयोगवश नहीं हैं, बल्कि एक कानूनी और राजनीतिक ढांचे में निहित हैं जो यहूदी प्रभुत्व को प्राथमिकता देता है, जो रंगभेद के लक्ष्य को दर्शाता है कि अलगाव और असमानता के माध्यम से नस्लीय नियंत्रण को बनाए रखा जाए।

प्रतिवाद और उनका खंडन

इज़राइल की लोकतांत्रिक स्थिति के समर्थक अक्सर इसके चुनाव, स्वतंत्र न्यायपालिका, और knesset में अरब MKs की उपस्थिति को लोकतंत्र के सबूत के रूप में इंगित करते हैं। हालांकि, उपरोक्त व्यवस्थित असमानताएं और दमन इन तत्वों को कमजोर करते हैं। चुनाव, हालांकि नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं, तब समान राजनीतिक शक्ति में तब्दील नहीं होते जब अरब MKs को प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है और उनके समुदायों को हाशिए पर रखा जाता है। न्यायपालिका, हालांकि कभी-कभार फलस्तीनी अधिकारों के पक्ष में फैसले देती है, ने राष्ट्र-राज्य कानून और निष्कासन कानून जैसे कानूनों को बरकरार रखा है, जो यहूदी सर्वोच्चता को स्थापित करते हैं। इसके अलावा, अरब MKs की उपस्थिति तब अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व के बराबर नहीं होती जब उन्हें उनके राजनीतिक विचारों के लिए नियमित रूप से निशाना बनाया जाता है, जैसा कि निलंबन और निष्कासन के प्रयासों से स्पष्ट है।

एक और तर्क यह है कि इज़राइल की कार्रवाइयां सुरक्षा खतरों, जैसे फलस्तीनी आतंकवाद, के जवाब में हैं। हालांकि सुरक्षा चिंताएं वास्तविक हैं, वे फलस्तीनियों पर थोपी गई व्यापक भेदभाव और सामूहिक दंड को उचित नहीं ठहरातीं। गाजा की नाकाबंदी, वेस्ट बैंक का सैन्य कब्जा, और इज़राइल के भीतर असहमति का दमन लक्षित सुरक्षा उपायों से परे जाता है, एक ऐसी नियंत्रण व्यवस्था बनाता है जो जातीयता के आधार पर एक समूह को दूसरे पर प्राथमिकता देता है—रंगभेद की एक परिभाषित विशेषता, न कि खतरों का लोकतांत्रिक जवाब।

निष्कर्ष

इज़राइल की नीतियां और प्रथाएं—व्यवस्थित भेदभाव, असहमति का दमन, और अधिकारों में स्पष्ट असमानताएं—लोकतंत्र की तुलना में रंगभेद के साथ अधिक सरेखित हैं। कानूनी ढांचा, जैसा कि राष्ट्र-राज्य कानून और निष्कासन कानून में देखा

गया है, समान नागरिकता पर यहूदी पहचान को प्राथमिकता देता है, जबकि फलस्तीनी MKS और नागरिकों के साथ व्यवहार बहिष्कार और दमन का एक पैटर्न दर्शाता है। फलस्तीनियों की जीवित वास्तविकता, चाहे गाजा में, वेस्ट बैंक में, या इज़राइल के भीतर, अलगाव और अभाव की है, जो यहूदी इज़राइलियों को दिए गए अधिकारों के साथ तीव्र विरोधाभास में है। ये तत्व, जो मानवाधिकार संगठनों द्वारा दस्तावेज किए गए और हाल के घटनाओं द्वारा समर्थित हैं, इज़राइल को एक लोकतंत्र के रूप में प्रस्तुत करने की कथा को चुनौती देते हैं और इसके बजाय एक रंगभेदी राज्य की तस्वीर पेश करते हैं, जहां व्यवस्थित असमानता और प्रभुत्व राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को परिभाषित करते हैं। सच्चा लोकतंत्र सभी के लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय की मांग करता है, जो सिद्धांत इज़राइल की वर्तमान व्यवस्था फलस्तीनियों के लिए बनाए रखने में विफल रहती है।